राजस्थान पत्रिका

सम्पादकीय

सत्ता की सौदेबाजी

जिस तरह विचारधारा और विश्वासघात में तालमेल नहीं हो सकता, उसी तरह सिद्धांतों और सौदेबाजी में भी कोई समीपता नजर नहीं आती। देश की राजनीति ने यूं तो पहले अनेक बार विचारधारा के बिखराव को भी देखा है और दोस्ती के बीच विश्वासघात को भी महसूस किया है। सिद्धांतों की दुहाई देने वालों को सिद्धांतों से भटकते भी देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो खेल चल रहा है वह विचारधारा और सिद्धांतों की राजनीति से सौदेबाजी और लेन-देन की राजनीति में तब्दील होता नजर आ रहा है। ढाई दशक तक विचारधारा और सिद्धांतों के नाम पर राजनीति करने का दावा करने वाली भाजपा और शिवसेना अब सौदेबाजी और लेन-देन की राजनीति में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। बहुमत की दहलीज से दूर खड़ी भाजपा की सरकार तो बन गई लेकिन उसे अब तय करना है कि सरकार अल्पमत की बनानी है या बहुमत की?

भाजपा, शिवसेना या अन्य दल अगर इस मुगालते में हैं कि जनता उनकी नीति विहीन राजनीति और अवसरवादी पैंतरेबाजी को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी तो यह उनकी भारी भूल होगी।

भाजपा की धुरविरोधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना को रोकने के लिए पहले ही बिना मांगे समर्थन दे चुकी है। ये ऐलान भी कर चुकी है कि बहुमत साबित करते समय वह सदन से वाकआउट भी कर सकती है। मतलब सीधा और साफ है कि भाजपा बिना शिवसेना के अल्पमत सरकार चला सकती है। भाजपा का एक धड़ा इसी रास्ते पर चलने का दबाव बना रहा है लेकिन इससे पार्टी कठघरे में खड़ा होने से बच नहीं सकती। जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताया, क्या उसके समर्थन से सरकार चलाना मतदाताओं के गले उतरेगा? पार्टी ऐसा नहीं करती तो शिवसेना से सौदेबाजी करनी पड़ेगी। उसी शिवसेना से जिसके साथ विधानसभा चुनाव में जमकर 'तू-तू, मैं-मैं' हुई। जिसने भाजपा के शीर्ष नेता नरेन्द्र मोदी के पिता की जन्मपत्री तक खोल डाली और पार्टी पर कांग्रेस से भी तीखे प्रहार करने से नहीं चूकी। बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुध लेहि का नाम ही राजनीति रह गया है तो महाराष्ट्र में सौदेबाजी का खेल दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री पद की संख्या को लेकर भी सौदेबाजी हो रही है और विभागों को लेकर भी। भाजपा, शिवसेना या अन्य दल अगर इस मुगालते में हैं कि जनता उनकी नीति विहीन राजनीति और पैंतरेबाजी को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी तो यह उनकी भारी भूल होगी। अब जनता न तो बर्दाश्त करती है और न ही सत्ता की सौदेबाजी को अनदेखा करती है। बस, समय का इंतजार करती है। सभी दलों ने समय-समय पर यह देखा भी है। खेद की बात यह है कि इसके बावजूद राजनीतिक दल सबक नहीं सीखते।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। - वाल्तेयर

बात-करामात

गड़ गड़ हाल

कसम कच्ची और पक्की की! हमारा दिल करता है कि इस देश के आला नेताओं को , सभी पुराने पंथ प्रधानों को, राज्य के भूख-प्यास विभाग के मंत्री और उन सारे आर्थिक विशेषज्ञों को किसी दिन सरकारी देसी ठेके पर ले जाना चाहते हैं? अरे! अरे! यह क्या? आप तो पूरी बात सुने बगैर ही हमारे पीछे पड़ गए। नहीं जनाब नहीं। हमारा कोई गलत इरादा नहीं । हम तो बस इन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि जिस देश के विकास का डंका आप लोग अपने भाषणों में पीटते रहते हैं उस देश के आम मजदूर, खेतीहर, रिक्शेवाले, मेहनतकश की असली हालत क्या है? चलिए छोड़िए हुजूर। इतने बड़े-बड़े आदमियों को समझाने की हमारी औकात ही क्या है लेकिन आपके पहलू में अगर दिल धड़कता है और आपको भी पराए दुख-दर्द देखने की बेचैनी है तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए किसी नजदीकी सरकारी कच्ची के ठेके पर। ये देखिए- यह एक रिक्शे वाला है। बदन पर एक पाव भी मांस नहीं बचा है। यह आदमी सुबह-सुबह बीस रुपए में ठर्री खरीदता है, एक सांस में गड़-गड़-गिटक जाता है और अपने शरीर की सारी ताकत रिक्शे के पैडिलों पर मार कर दो रोटी के जुगाड़ के लिए चल देता है। यह सफाई करने वाला है। इसे गटर में उतरना है पर क्या कोई इनसान होशो-हवास में गटर की गंदगी में उतर सकता है? जी नहीं। इसलिए यह पहले पीकर

नशेबाज तो इस दुनिया में हर इंसान है। किसी को सत्ता का नशा है तो किसी को सौन्दर्य का। कोई धन के सुरूर में है तो किसी को बाजुओं का गरूर है।

अपने होश गंवाएगा और फिर गटर साफ करेगा। ये मजदूर है। दिन भर इसे हाड़- तोड़ मेहनत करनी है। यह भी दिन भर परिश्रम करने की ताकत चार घूंट से पाना चाहता है। और ये जनाब शरीर से विकलांग हैं। चौराहे पर भीख मांगते हैं लेकिन इन्हें भीख देने वाले कम, नसीहत देने वाले ज्यादा मिलते हैं। सो थोड़ी-सी पीकर बेशर्म बनना चाह रहे हैं। ये सब लोग इसी शहर के बाशिन्दे हैं जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हमारी सरकार जद्दोजहद कर रही है।

आप कह सकते हैं कि ये सब शराबी कबाबी हैं और आदतन नशेड़ी हैं। नशेबाज तो इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान होता है। किसी को सत्ता का नशा है तो किसी को सौन्दर्य का। कोई रुपए पैसे के सुरूर में है तो किसी को बाजुओं का गरूर है। लेकिन जरा यह तो सोचिए कि इनकी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? लीजिए , आप तो खामखां नाराज होकर हम पर ही उलटे नशे में होने का इल्जाम लगाने लगे। चलिए यह भी मान लेते हैं क्योंकि होशो-हवास में इन दर्दमंदों का दर्द समझा ही नहीं जा सकता। – *राही*

प्रत्यक्ष : सिंहासन

महासमर 2258

छोड़िए भी।' देवकी ने उन्हें इस चर्चा से विरत करना चाहा, 'आपको क्या लेना है, इन विवादों से।' 'सत्य है कि मुझे कुछ नहीं लेना राजनीति और सत्ता के इस बंटवारे से।' वसुदेव का स्वर पर्याप्त हताश था 'किंतु मैं यादवों की सुख-समृद्धि से तो उदासीन नहीं हूं। संसार में धर्म की पराजय तो नहीं देखना चाहता मैं। यादवों की जिस स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए, मैंने अक्रूर के समान कंस से समझौता नहीं किया। एक के पश्चात् एक अपने नवजात शिशुओं को उस राक्षस के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते देखा, उस स्वतंत्रता और स्वाभिमान को अब मैं सत्ता लोलुप, स्वार्थी लोगों की झोली में तो नहीं डाल सकता।' वसुदेव रुके और जैसे दुगने आवेश के साथ बोले, 'जब शत्रुओं के पग तले इनका कंठ दबा हुआ था, अपना बलिदान देने वाला नेता चाहिए था, तब तो कृष्ण प्यारा था इन सबको। अब इन्हें कृष्ण की कोई नीति रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उन्हें सत्ता का अबाध भोग नहीं करने देता। उनके पापों के मार्ग में आड़े आता है कृष्ण।'

अर्जुन ने मातुल को कभी इस प्रकार आवेश में बोलते नहीं सुना था। कोई विशेष बात ही होगी अन्यथा यह उनका स्वभाव नहीं था।

'कोई विशेष बात मातुल?' अर्जुन को लगा कि प्रश्न पूछने के लिए वह उचित शब्द भी ढूंढ नहीं पा रहा है। 'विशेष बात क्या होनी है पुत्र! सदा के समान मनुष्य के लोभ, स्वार्थ और मूर्खता की गाथा है जो इस समय यादवों पर घटित हो रही है।' वसुदेव बोले, 'जब तक कंस और जरासंध जीवित थे, सबको लग रहा था कि सब कुछ उनका ही है। और किसी का कुछ भी नहीं है। तब किसी ने उनसे नहीं पूछा कि मथुरा का राज्य और यादवों की संपत्ति उनकी ही क्यों है किंतु अब वे नहीं हैं तो प्रत्येक यादव सोच रहा है कि द्वारका का राज्य उसी को क्यों नहीं मिल जाता, सत्ता उसके हाथ में क्यों नहीं आ जाती, स्यमंतक मणि उसकी मुट्ठी में बंद होकर क्यों नहीं रहती? सबको बहुत जल्दी है अधिकार पाने की, धनी होने की, अपने ही समाज को और अपने ही परिजनों को लूटने की। पहले तो एक जरासंध था जो यादवों के धन को मथुरा से बाहर ले जाता था और यादव कंगाल होते जाते थे। अब तो अनेक जरासंध हो गए हैं। कितने ही यादव हैं जो यादवों के धन को उचित-अनुचित साधनों से हथियाकर विभिन्न देशों और राज्यों में अपनी तथा अपने विदेशी मित्रों की कोठियों में संचित कर रहे हैं ताकि न महाराजा उग्रसेन का उस पर कोई अधिकार रहे, न सुधर्मा सभा का।'

अर्जुन के लिए इसमें से बहुत कुछ नया था। न तो उसने कभी यादवों की राजनीति में रुचि ली थी, न कभी कृष्ण ने ही उससे ऐसी कोई चर्चा की थी।

'पर महाराज उग्रसेन से किसी का क्या विरोध हो सकता है?' उसने कुछ चकित भाव से पूछा।

'विरोध! विरोध क्या होना है पुत्र!' वसुदेव हंसे, 'कुछ लोगों को राज्य पाने की बहुत जल्दी है। उन्हें लगता है कि महाराज बहुत वृद्ध हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि ये सिंहासन त्याग दें।'

अर्जुन ने मातुल की ओर देखा भर। कहा कुछ भी नहीं। 'महाराज सिंहासन त्याग भी दें तो उत्तराधिकार किसको मिले? कौन निर्णय करे कि महाराज का उत्तराधिकारी कौन है?''महाराज उग्रसेन और कौन?''पर यदि महाराज का निर्णय उनके पक्ष में नहीं हुआ तो।' वसुदेव बोले, 'इसलिए वे यह अधिकार महाराज को नहीं देना चाहते।'

क्रमशः – नरेन्द्र कोहली

स्पॉटलाइट

खर्च कटौती : यूपीए सरकार की तरह एनडीए ने भी शुरू किया खर्चों में कटौती का अभियान

जारी रहे यह अंकुश

एनडीए सरकार ने भी खर्चों में कटौती के लिए कुछ विशेष प्रयास शुरू किए हैं। सरकारें समय-समय पर इस प्रकार के कदम उठाती रही हैं। पर, अभी तक का अनुभव यह बताता है कि अधिकांशतः सारे प्रयास कागजों पर ही रह जाते हैं। इसलिए बदलाव के वादे के साथ आई नई सरकार के इन कदमों के प्रति जहां एक आशा का भाव है तो वहीं पुरानी उदासीनता भी है। जरूरत इस बात की है कि सरकार सिर्फ तात्कालिक कदम ही नहीं उठाए उनको लागू करने के प्रति दूरगामी कटिबद्धता भी दिखाए। सरकार के इन मितव्ययिता के उपायों के बारे में क्या कहते हैं जानकार, पढ़िए आज के स्पॉटलाइट में।

कड़े कदमों की जरूरत

प्रोफेसर तापस के. सेन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी

मोदी सरकार ने खर्चे कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सामान्य कदम हैं, स्टैंडर्ड कदम हैं। उन्हें असाधारण कदम नहीं कहा जा सकता। पुरानी सरकारें भी इस तरह के कदम उठाती रही हैं। पुराने अनुभव यही कहते हैं कि इन उपायों से 10-12 प्रतिशत खर्चा कम हो जाता है। पर इस तरह के सारे उपाय थोड़े समय के लिए ही होते हैं और इनका असर भी कुछ समय तक ही रहता है। अधिक से अधिक छह से नौ महीने तक इन कदमों को जारी रखा जा सकता है। ये उपाय लंबे समय तक जारी नहीं रखे जा सकते। ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जो दीर्घकालीन हों और जिनके असर भी दूरगामी हों।

...मूल बीमारी का इलाज करना होगा

जरूरत इस बात की है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं को संबोधित किया जाए। यह देखने की जरूरत है कि कहां खर्चा ज्यादा और कहां कम है। उसी को संतुलित करने की जरूरत है। अभी तक सिर्फ समस्याओं का बाहरी इलाज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बुखार है तो क्रोसीन देकर उसका बुखार तात्कालिक रूप से तो कम किया जा सकता है, पर वह उसका उपचार नहीं है। उपचार तो तभी होगा जब यह पता लगाया जाए कि बुखार क्यों आया और फिर उन कारणों को खत्म करने के लिए दवा दी जाए।

मोदी सरकार अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने की दिशा में कुछ असाधारण कदम नहीं उठाती है तो उसे राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे बहुमत से मिले बदलाव के जनादेश का पूरा फायदा उठाना ही चाहिए।

हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा असंतुलन आता है सब्सिडी के खर्चे से। इसमें भी अब पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी तो कुछ हद तक नियंत्रण में आई है पर खाद और खाद्य की सब्सिडी तो अभी भी बहुत ज्यादा है। इनमें कटौती किए बिना तो सरकार को अपना खर्चा कम करना संभव नहीं होगा। एक और बिंदु जो इस सरकार को ध्यान रखना होगा कि वह नए वेतन आयोग के लिए दबाव डाल रहे लोगों की मांगों पर ध्यान न दे। अब तक का अनुभव यही बताता है कि जब भी वेतन बढ़ाए गए हैं, तो वह बढ़ोतरी काफी अधिक हुई है। इस कारण से केंद्र और राज्यों दोनों का ही वित्त प्रबंधन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो जाता है। सरकारों का इसका पूर्वाभास भी होता है पर सरकारें सरकारी कर्मियों की लॉबी के आगे झुक जाती हैं।

...सख्ती और निगरानी जरूरी

सरकारी कर्मियों के अपव्यय जैसे उनके वाहनों और दूसरी सुविधाओं का खर्चा, उनके दुरुपयोग का मुद्दा भी कई बार जोर-शोर से उठाया जाता है। चीन जैसे देशों ने अभी इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी हैं। पर इस बारे में कानून बनाने से कुछ होगा ऐसा लगता नहीं। वह इसलिए, क्योंकि कानून तो पहले ही बने हुए हैं और वाहनों या सुविधाओं का सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी हित में उपयोग गैर कानूनी ही है। जरूरत है इन कानूनी प्रावधानों को लागू करने की। अभी तक तो ऐसे विषयों पर अधिकारियों से कुछ पूछताछ होती नहीं, इसलिए उनमें डर है ही नहीं। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कर अगर उदाहरण पेश किया जाए तो इस दिशा में कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। खर्चा कम करने के लिए मोदी सरकार को इस उपाय पर भी आगे बढ़ना चाहिए।

...सब्सिडी पर सोचना होगा

पर जिन उपायों से कुछ ठोस सफलता मिलेगी वो उपाय तो सब्सिडी आदि के मोर्चे पर ही हैं। यहां करोड़ों करोड़ रुपये के खर्च का सवाल है। इनका असर भी दूरगामी होगा। पुरानी सरकार की तुलना में नई सरकार इस मुद्दे पर काफी बेहतर स्थिति में है। अगर पुरानी सरकार ये सब्सिडी खत्म करने की दिशा में कदम उठाती तो उसको उसकी काफी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती, पर मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं है।

मिला है बदलाव का जनादेश

उसके सामने तो खुला मैदान है। इस सरकार को तो जनता लाई ही इसलिए है कि वह कुछ असाधारण कदम उठाए। इसलिए यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि अगर मोदी सरकार अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने की दिशा में कुछ असाधारण कदम नहीं उठाती है तो उसे राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार को जनता ने जो इतना भारी बहुमत दिया है उसका फायदा उन्हें उठाना चाहिए। इस सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश जनता ने बदलाव के लिए ही दिया है, पुरानी नीतियों की निरंतरता के लिए नहीं। इसलिए इस मुद्दे पर मोदी सरकार को कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

लागू करना चुनौती

वी सुंदर राव, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स, हैदराबाद

सरकार ने जो खर्चा बचाने की दिशा में जो उपाय किए हैं वो बेहतर तो हैं पर असली समस्या क्रियान्वयन की है। अभी तक पुरानी सरकारों ने जो भी इस प्रकार के कदम उठाए थे वो सभी कागज पर ही रह गए थे। पर अगर सरकार इन उपायों को क्रियान्वित करती है तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। अनुमान है कि सरकार का जो बजट शेष है उसमें 15 प्रतिशत से अधिक की बचत की जा सकती है। पुरानी सरकार में तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ही 100 करोड़ से अधिक रुपये तो विदेशी यात्राओं पर ही खर्च कर दिए थे। इस तरह का खर्चीला आचरण किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता।

जागेगा जिम्मेदारी का भाव

गुरुचरण दास , वरिष्ठ टिप्पणीकार

नौकरशाही को समय की बचत और सदुपयोग की दिशा में प्रेरित करने के बाद मोदी सरकार अब पैसे की बचत और सदुपयोग के लिए प्रयास कर रही है।

मोदी सरकर ने हाल में जो कदम उठाए हैं वो अच्छे उपाय हैं। खर्च के बारे में इस तरह की जागरूकता होनी ही चाहिए। इस प्रकार के तरीकों से नौकरशाही को अभिप्रेरित किया जा रहा है। एक जिम्मेदारी का भाव पैदा किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से जिस तरह से आम जन में जिम्मेदारी का भाव पैदा किया गया है उसी प्रकार का स्व जिम्मेदारी का भाव अब खर्चे के विषय में नौकरशाही में जगाने की कोशिश की जा रही है। पर यह जरूरी नहीं, यह तो अनिवार्य होना चाहिए।

सरकारी महकमों में बर्बादी और अपव्यय होता भी बहुत है। इसलिए इस प्रकार के उपायों से इस तरह का भाव जागना चाहिए कि सरकार का पैसा भी हमारा ही पैसा है। वक्त के प्रति पाबंदी भी इसी दिशा में किया गया उपाय है। सरकारी कर्मचारी कितने बजे आते हैं, कितना समय लंच में लेते हैं और कितने बजे जाते हैं। इससे समय की बचत और सदुपयोग की दिशा में भी मोदी सरकार ने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है। इसके पीछे भावना यही है कि पूरी प्रणाली में एक जवाबदेही और जिम्मेदारी का संचार किया जा सके।

सब्सिडी भी निश्चित रूप से इस दिशा में एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी कम करने की दिशा में तो आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया है। धीरे-धीरे अब खाद्य और रसोई गैस आदि के मुद्दे पर भी कैश ट्रांसफर पर सरकार को आना चाहिए, जिससे सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी मिले जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं, उनका उपयोग इस लक्षित सब्सिडी के हस्तांतरण में भी किया जा सकता है। अभी तो हाल यह है कि रसोई गैस पर आधी से ज्यादा सब्सिडी तो मध्यम वर्ग के हिस्से में चली जाती है जिसे उसकी जरूरत नहीं है।

कुछ नया नहीं है

सरकार ने जो उपाय किए हैं उनमें कुछ नया नहीं है। सरकारें जब किफायत के उपाय करती हैं तो इसी तरह के कदम उठाती हैं। फाइव स्टार होटलों में बैठक मत करो, प्रथम श्रेणी में यात्रा मत करो, वाहनों का निजी हित में प्रयोग न करो आदि। पर इनसे कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। बल्कि ये तो वे उपाय हैं जिनको सरकार को अपनी कार्यप्रणाली का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। इनको किसी असाधारण उपायों की तरह पेश न कर सरकार के कामकाज का सामान्य हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। बिना कोई ज्यादा शोरगुल किए बिना। बल्कि सरकार को दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए जैसे टैक्स संग्रहण बढ़ाने के लिए कर दायरा कैसे बढ़े, रेलवे की सेहत कैसे सुधारें। इन प्रयासों का असर भी ज्यादा होगा और ज्यादा समय तक रहेगा भी।

प्रोफेसर अभिजीत सेन
पूर्व सदस्य, योजना आयोग

मंत्रियों को भी शामिल करें

अविनाश चन्द्र, सीसीएस

आर्थिक सुधार की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने गैर योजनागत खर्चों में 10 फीसदी की कटौती का फैसला लिया है। यह कदम स्वागत योग्य है। सरकार के इस निर्णय से इस मद में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। मोदी सरकार का यह फैसला दूरदर्शी अवश्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी अलग है। दरअसल, सरकार द्वारा यह फैसला बजट के दौरान राजकोषीय घाटे को कम करने के निर्धारित लक्ष्य से भटकने का परिणाम ज्यादा है। वित्तमंत्री ने पिछले बजट के दौरान राजकोषीय घाटे को मौजूदा वर्ष में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 तक 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया था। लेकिन बजट में तय घाटे की सीमा का 80 प्रतिशत हिस्सा अप्रेल से सितंबर के बीच ही खर्च हो गया और अगले छह महीनों में खर्चने के लिए महज 20 प्रतिशत बजट ही शेष रह गया था। जबकि यूपीए 2 के कार्यकाल में पिछले वर्ष प्रथम छमाही में तय घाटे का 76 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ था। हालांकि तब की मनमोहन सिंह सरकार ने भी सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला किया था। यदि वर्तमान सरकार अभी भी नहीं चेतती तो राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य पहले साल में ही अधूरा रह जाता और बढ़ती महंगाई से राहत एक बार फिर दूर की कौड़ी साबित हो जाती। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि शेयर बाजार में उछाल और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में कमी आने के बाद भी चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में ही राजकोषीय घाटे की तय सीमा के कुल हिस्से का 80 प्रतिशत से अधिक खर्च हो जाना कहीं ना कहीं सही संकेत नहीं है।

सरकार को मंत्रियों के खर्चों में भी कटौती की दिशा में सोचना चाहिए। अक्टूबर महीने में एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सरकार से प्राप्त सूचना में पता चला था कि मोदी सरकार के नवनिर्वाचित 106 सांसद आईटीडीसी के सम्राट होटल, जनपथ और अशोका होटल जैसे फाइव स्टार होटलों में रह रहे थे। सांसदों को इन होटलों में ठहराने का खर्च ही प्रतिमाह लगभग 2.5 लाख रुपए था। अच्छा होता कि सरकार शुरू से ही ऐसी बातों पर ध्यान देती। मोदी सरकार को नौकरशाहों की प्रथम दर्जे की हवाई यात्रा, फाइव स्टार होटलों में सेमिनार व कांफ्रेंस करने और नए वाहनों की खरीद पर रोक लगाने के साथ ही साथ मंत्रियों की ऐसी गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों को विदेशी यात्रा के दौरान बेवजह की भीड़ को अपने साथ ले जाने से बचने की सलाह दे रखी है।

एक ओर केन्द्र में भाजपा सरकार खर्चों में कटौती कर रही हैं, वहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में शपथ ग्रहण की। भले ही भाजपा कुछ करोड़ का खर्चा बता रही हो लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे भव्य कार्यक्रमों से केन्द्र सरकार के मितव्ययिता के संदेश को धक्का लगता है।

तात्कालिक नहीं स्थायी भाव हो

अच्छा होता कि वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ इस वित्त वर्ष के दौरान ही नहीं, सदैव के लिए नौकरशाहों और मंत्रियों की प्रथम श्रेणी यात्रा पर रोक लगा दें। वह घोषणा करें कि आगे से कोई भी अफसर या मंत्री प्रथम दर्जे और बिजनेस क्लास की यात्रा नहीं करेगा और उन्हें भी आम जनता के साथ साधारण श्रेणी की ही यात्रा करनी पड़ेगी। इससे जनता में न केवल सरकार के प्रति सम्मान और बढ़ेगा बल्कि खर्चे में कटौती भी हो सकेगी। अति आवश्यकता ना होने पर सरकारी विभागों में एक साल से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को न भरने का फैसला भी अत्यंत सराहनीय है। स्पष्ट है कि जिन पदों के एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहने के बावजूद सरकारी कामकाज पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो आगे भी उन कर्मचारियों के बगैर काम चल सकता है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जॉब क्रिएशन की बजाए स्किल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं। खर्चों में कटौती के इन उपायों का असल प्रभाव कितना पड़ा और नौकरशाह सरकारी नीतियों पर कितना अमल होने देते हैं यह तो वर्ष के अन्त में ही पता चलेगा लेकिन इस कदम का सकारात्मक संदेश अवश्य गया है।